धार्मिक एकता की मिथ्या

लेखक- सी. राजा मोहन (निदेशक, इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

19 सितम्बर, 2019

"कश्मीर पर भारत के निर्णय के लिए कई मुस्लिम देशों की प्रतिक्रियाओं से पता चलता है कि राजनीतिक और आर्थिक हित ही राष्ट्रों को एक दूसरे से बांधते हैं न की विचारधाराएं।"

जैसा कि पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर की स्थिति को बदलने के लिए पिछले महीने भारत के फैसले के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को लामबंद करने के लिए संघर्ष किया, दुनिया के मुस्लिम देशों से समर्थन की कमी के कारण इसे काफी निराशा का सामना करना पड़ा। लंबे समय से पाकिस्तान के कट्टर समर्थक के रूप में होने के बावजूद संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब ने भारत के इस कदम की आलोचना नहीं की, जिसके कारण इसे मुस्लिम दुनिया में आलोचना का सामना करना पड़ा।

बहुत जल्द ही पाकिस्तान में बहस को अंजाम देने वाले यह समझ गये कि यूएई और सऊदी अरब का भारत में बढ़ते आर्थिक दांव पाकिस्तान के धार्मिक एकजुटता से काफी बड़ा है, जिसके कारण ही कश्मीर के प्रश्न पर ये दोनों देश चुप रहे। पाकिस्तानी विश्लेषकों ने दिल्ली और इस्लामाबाद के बारे में खाड़ी में अलग-अलग दृष्टिकोणों की तुलना की है। यूएई और सऊदी अरब दिल्ली को एक मूल्यवान व्यापारिक साझेदार के रूप में देखते हैं और इस्लामाबाद को एक आर्थिक लाभ के इच्छुक के रूप में देखते है जो आर्थिक संकट आने पर उन्हें याद करता है।

पाकिस्तान का अपना राष्ट्रीय अनुभव उस प्रस्ताव को नकार देता है, जिसमें दुनिया के मुसलमान एक सुसंगत राजनीतिक समुदाय का गठन करते हैं। धर्म लगभग एक ही देश के लोगों को बांधने में सक्षम नहीं हो पाता है, वह संपूर्ण राष्ट्र को एकजुट कैसे कर सकता है?

पाकिस्तान ने 1947 में दक्षिण एशियाई मुसलमानों की मातृभूमि के रूप में अपनी जगह बनाई थी, लेकिन पाकिस्तान ने 25 वर्षों के भीतर ही अपनी पूर्वी शाखा को खो दिया। 1971 के अंत में बांग्लादेश के निर्माण में, भाषाई पहचान की ताकत धार्मिक आत्मीयता के अनुमानित वजन पर हावी रही। बलूच, पश्तून और मोहजिर समुदायों के बीच मौजूदा राजनीतिक अशांति पाकिस्तान में साझा इस्लामिक पहचान को बदल देती है। तो अब सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान शिया और अहमदी जैसे मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करता है।

चीन राष्ट्रों के बीच साझेदारी को आकार देने में धर्म के सीमित महत्व का दो उदाहरण प्रदान करता है। पहला है कम्युनिस्ट चीन, जो मुस्लिमदुनिया नहीं है ने पिछले कुछ हफ्तों में कश्मीर पर पाकिस्तान के लिए समर्थन बढ़ाया है। इसके पीछे क्या कारण है उसे समझना मुश्किल नहीं है। भारत को संतुलित करने में चीन का पाकिस्तान के साथ साझा हित है। और बीजिंग कश्मीर में विवादों का एक पक्ष भी है।

इस्लामिक एकजुटता से ऊपर राष्ट्रीय हितों को रखने के लिए इस्लामाबाद की इच्छा चीन के सुदूर पश्चिमी प्रांत झिंजियांग में उइगर मुसलमानों के बीजिंग के व्यवहार के जवाब में देखी जा सकती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, जो कश्मीर में भारत के उत्पीड़न पर एक शेर की तरह दहाड़ रहे हैं, से जब चीन में मुसलमानों के दमन के बारे में पूछा जाता है तो भीगी बिल्ली बन जाते है। यदि धार्मिक एकजुटता का आह्वाहन केवल सीमित मूल्य में है, तो पाकिस्तान इसके साथ क्यों जुड़ा रहता है? एक ऐसा देश जो इस्लाम

के नाम पर भारत से अलग हुआ, उसके लिए धार्मिक एकजुटता पर टिका रहना एक राजनीतिक मिशन के संबंध में एक हथियार की तरह है। विभाजन के बाद, पाकिस्तान ने मध्य पूर्व के साथ इस्लामी एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया। इस्लाम के लिए पाकिस्तान के उत्साह को देखते हुए एक बार मिस्र के राजा फारूक ने कथित तौर पर मजाक में कह दिया था कि उन्हें नहीं पता था कि इस्लाम 14 अगस्त, 1947 को पैदा हुआ था।

सभी देशों के पास अपने मिथक होते हैं और वास्तविकता को सामने नहीं आने दे सकते। बेशक, भारत भी इससे अछूता नहीं है। यदि पाकिस्तान इस्लामी एकता के मिथ्या का पालन करता है, तो भारत का भी अपना मिथक है - उदाहरण के लिए, यह विचार कि 'हेजेमोनिक वेस्ट' (जो दूसरे राष्ट्रों पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करता हो) के खिलाफ 'वैश्विक दक्षिण' के साथ एकजुटता इसकी विदेश नीति का एक मूलभूत सिद्धांत है।

2005-08 के दौरान, अभी डेढ़ दशक पहले, भारत ईरान के विवादास्पद परमाणु कार्यक्रम का बचाव करने के लिए निर्धारित दायित्व के लिए अपने स्वयं के परमाणु हितों को छोड़ने के लिए काफी करीब आया था। जैसा कि ऐतिहासिक असैन्य परमाणु पहल पर अमेरिकी बहस तेहरान के खिलाफ वाशिंगटन के दबाव से उलझ गई थी, दिल्ली में एक मजबूत मांग शुरू हो गयी थी कि भारत गैर एकजुट एकजुटता के नाम पर ईरान के लिए खड़ा हो। मनमोहन सिंह सरकार इस प्रलोभन का विरोध करने में मुश्किल से कामयाब हुई थी। 2015 में अमेरिका के साथ परमाणु समझौते को स्वीकार करने के तुरंत बाद ईरान के इस कदम से दिल्ली का फैसला रद्द हो गया था।

इस्लामिक प्रिज्म के जरिए खाड़ी को देखने में पाकिस्तान अकेला नहीं है। भारत ने भी बहुत कुछ ऐसा ही किया। बहुत लंबे समय से, दिल्ली ने यूएई और सऊदी अरब की विदेश नीतियों का आकलन करने में इस्लामी कारक को निर्धारित किया था और उन्हें 'पाकिस्तान समर्थक' के रूप में ब्रांडेड किया था। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने 1982 और 2010 के बीच संयुक्त अरब अमीरात और 1981 से 2015 के बीच सऊदी अरब का दौरा नहीं किया था। जब भारत ने इन देशों के साथ रुचि आधारित जुड़ाव शुरू किया, तो द्विपक्षीय संबंधों में तेजी से सुधार हुआ।

20वीं शताब्दी में, कम्युनिस्ट अंतर्राष्ट्रीयतावाद, पैन-एशियनिज्म, पैन-अरबिज्म, पैन-इस्लामिज्म और थर्ड वर्ल्डिज्म जैसी कई पारलौकिक विचारधाराओं ने दुनिया को उलझा कर रख दिया था। लेकिन इनमें से कोई भी एक ऐसी दुनिया में कायम नहीं रह सकता है, जो नेशन स्टेट (एक संप्रभु राज्य जिसमें से अधिकांश नागरिक या विषय भी ऐसे कारकों द्वारा एकजुट होते हैं जो एक राष्ट्र को परिभाषित करते हैं, जैसे भाषा।) के आसपास स्थापित हो।

द कॉमिन्टर्न, अरब लीग, ऑर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन और गुटनिरपेक्ष आंदोलन, सभी बेकार हो गए हैं। सामूहिक पहचान के प्रति राष्ट्रीय वफादारी की घोषणा लगभग हर समय की जाती है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि राष्ट्र अपने विशेष हितों के अनुरूप बड़ी पहचानों को लागू करना जारी रखेंगे। चीनी नेता शी जिनपिंग ने 'एशियाइयों के लिए एशिया' के बारे में बात की है। यह अमेरिका को एशिया से बाहर निकलने का एक अच्छा तरीका है। लेकिन कई एशियाई देशों को चीन के बढ़ने का भी डर है और इसके बजाय अमेरिका को एक संतुलन शक्ति के रूप में रहना होगा। रिसेप तईप एर्दोगन खुद को न केवल तुर्की के नेता बल्कि पूरे मुस्लिम विश्व के रूप में देखते हैं।

हालाँकि पाकिस्तान का इस्लामिक अंतर्राष्ट्रीयवाद व्यर्थ है, इस्लामाबाद को इस तरह खेलना बंद करने में मुश्किल होगी। किसी दिन भविष्य में, पाकिस्तान भारत के साथ सुलह को मान्यता दे सकता है, जिससे वह मध्य पूर्व, मुस्लिमदुनिया और उससे परे एक बड़ी भूमिका निभाने में सफल हो सकेगा।

GS World Committed to Excellence

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. **जम्मू-कश्मीर पर भारत के फैसले के खिलाफ धार्मिक एकजुटता के नाम पर पाकिस्तान के विरोध से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।**

   1. पाकिस्तान दक्षिण एशियाई मुसलमानों की मातृभूमि के रूप में अपनी जगह बनाई थी पर मुस्लिम देशों के समर्थन के अभाव में इस विरोध में निराशा का सामना करना पड़ा।
   2. इस्लामिक एकजुटता से ऊपर राष्ट्रीय हितों को रखने के रूप में मुस्लिम देशों का रूख दिखा क्योंकि धार्मिक एकजुटता सीमित मूल्य में है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन पाकिस्तान के विरोध के साथ तर्कसंगत है/हैं?

   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

Expected Questions (Prelims Exams)

1. **Consider the following statements related to Pakistan's protest in the name of religious solidarity against India's decision on Jammu and Kashmir-**

   1. Pakistan had made its place as the homeland of South Asian Muslims but due to lack of support from Muslim countries, this protest faced disappointment.
   2. Tendency to place national interests above Islamic solidarity of Muslim countries has been seen because religious solidarity has limited value.

   Which of the above statements are correct?

   (a) Only 1 (b) Only 2
   (c) Both 1 and 2 (d) Nither 1 nor 2

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: हाल ही में कश्मीर मुद्दे पर अरब इस्लामिक देशों का पाकिस्तान से दूर हटना इस बात को स्पष्ट करता है कि कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में धार्मिक एकता यूटोपियन विचार है। क्या आप इस कथन से सहमत है? अपने मत के पक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए। (250 शब्द)

Q. The recent withdrawal of Arab Islamic countries from Pakistan on the Kashmir issue makes it clear that religious unity in diplomacy and international relations is a utopian idea. Do you agree with this statement? Give an argument in favor of your opinion.
(250 Words)

नोट : 18 सितंबर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (c) होगा।